वर्ष 3 अंक 10 अक्तूबर 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

'एस्मो' के खिलाफ

प्रतिरोध अब संग्राम बन रहा है

केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हड़तालें

पूरा देश हड़तालों पर पाबन्दी लगाने वाले अनिवार्य सेवा सुरक्षा अध्यादेश (एस्मो) के खिलाफ प्रतिरोध और इसे वापिस लेने की मांग से गूंज रहा है. सत्रह अगस्त, जो काले दिवस के रूप में मनाया गया, सभी राज्यों के सभी उद्योगों और संस्थानों के मजदूरों के सभी हिस्सों द्वारा छेड़े गए प्रतिरोध संग्राम की शुरूआत भर था.

इसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्रमश 3, 11 तथा 14 सितम्बर को हुई प्रतिरोध हड़तालों (बंद) ने मजदूर वर्ग एवं जनवादी ताकतों में कांग्रेस (आई) सरकार के तानाशाही हमलों का कारगर तरीके से मुकाबला करने और जनवाद तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया उत्साह पैदा कर दिया है. इन तीनों ही राज्यों की वामपंथी और जनवादी ताकतों ने कांग्रेस (आई) के गुंडों और विघटनकारी शक्तियों की इन हड़तालों का विरोध करने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया.

जनता की इस आवाज ने संसद में सम्पूर्ण विरोध पक्ष द्वारा इस अध्यादेश को कानून बनाने से रोकने की लड़ाई का रूप ले लिया. हालांकि शासक पार्टी अपने निरे जंगली बहुमत के बल पर संसदीय लड़ाई जीत गई लेकिन औद्योगिक मजदूरों तथा निजी एवं पब्लिक दोनों ही क्षेत्रों के वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा की गई विशाल प्रतिरोध कार्यवाहियां उनके इस अध्यादेश को नामंजूर करने और अपने बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने के संकल्प को प्रतिबिंबित करती है.

देश के सभी हिस्सों से संयुक्त रैलियों, मोर्चों, गट मीटिंगों, पब्लिक मीटिंगों, काले बिल्ले लगाने, इश्तहार बांटने, ज्ञापन देन आदि की खबरें लगातार आ रही हैं. विभिन्न राज्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा दूसरे जन संगठनों को मिलाकर बनी राज्य अभिमान समितियों ने इस तानाशाहीपूर्ण कदम का प्रतिरोध करने के लिए जनता के विशाल हिस्सों को लामबन्द किया है.

आसाम में, पृथकतावादी आंदोलन के जहर और सरकार द्वारा केन्द्रीय रैली की इजाजत न देने के बावजूद, लगभग पूरे राज्य में विभिन्न पब्लिक एवं निजी क्षेत्रों के संस्थानों के मजदूरों द्वारा 17 अगस्त को काले बिल्ले लगाकर दिनभर प्रदर्शन और गेट मीटिंगें आदि करके बड़े पैमाने पर काला दिवस मनाया गया. आसाम में अभियान समिति राज्य में दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा, यहां तक कि इंटक भी अध्यादेश के खिलाफ खुलकर आई.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और पंजाब में राज्य अभियान समितियों ने संयुक्त आंदोलन करके इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की. सी. आई. टी. यू. की राज्य कमेटियों ने प्रतिरोध कार्यवाहियां करने के लिए मजदूरों तथा विभिन्न जनसंगठनों को लामबंद करके एकता कायम करने वाली ताकतों के रूप में काम किया. □

अखिल भारतीय प्रतिरोध व मांग दिवस—

तीन नवंबर

केरल, प० बंगाल और त्रिपुरा की जनता और मजदूरवर्ग को सीटू की बधाई

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 4, 12 व 15 सितंबर को क्रमशः ये बयान जारी किये हैं :

केरल : एस्मो (आवश्यक सेवा अध्यादेश) के खिलाफ प्रतिरोध में 3 सितंबर को एक दिवसीय कामयाब बंद आयोजित करने के लिए केरल के मजदूर वर्ग को सीटू बधाई देती है. केरल में केवल उन इनेगिनों को छोड़कर जो इंटक के कांग्रेस (आई) हिस्से के समर्थक हैं सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के 9 अगस्त को संपन्न राज्यस्तरीय सम्मेलन के आह्वान पर इतनी भारी भागीदारी दशाब्दियों के जुझारू संघर्षों, खून व कठिनाइयों द्वारा अर्जित हड़ताल के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मजदूरों का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करती है. केरल के मजदूर वर्ग ने, जिसे 1975 में आँतरिक एमर्जेंसी थोपने के खिलाफ एक दिन की कामयाब हड़ताल करने का श्रेय प्राप्त है, एक बार फिर जनता पर अधिनायकवादी शासन लादने के खिलाफ संघर्ष की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है.

यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ छुटपुट घटनाओं के कारण एटक का एक कार्यकर्ता मारा गया और अन्य कई मजदूर घायल हुए हैं. उस मजदूर की याद में, जिसने ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा में अपनी जान गवां दी, सीटू श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उसके शोकसंतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदना भेजती है.

सीटू समूचे देश के मजदूर वर्ग से यह अपील करती है कि वह पहले ही स्थापित एकता को कीमतवृद्धि व सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ और जनता पर अधिनायकवादी शासन लादने की सभी कोशिशों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित व मजबूत करे.

पश्चिम बंगाल : प० बंगाल की जनता व मजदूर वर्ग को जिसने आवश्यक सेवा अध्यादेश व कीमत वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध में सीटू व अन्य ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा 'बंगाल बंद' के आह्वान, जिसका समर्थन वाममोर्चा व कुछ अन्य दलों ने समर्थन किया था, में भारी मात्रा में भागीदारी की, सीटू बधाई देती है. सीटू पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार को भी बधाई देती है जिसने भड़काने वाली कार्यवाहियों के बावजूद शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए. इसे खास तौर से नोट करने की जरूरत है कि कांग्रेस (आई) व इंटक द्वारा किए गए बंद का विरोध करने के आह्वान को जनता ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बंद संपूर्ण रहा. यह इस बात का संकेत करता है कि पश्चिम बंगाल का मजदूर वर्ग व जनता न केवल केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार की कीमत वृद्धि व श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है बल्कि देश में एकदलीय अधिनायकवादी शासन को लाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रहा है.

पश्चिम बंगाल के मजदूरवर्ग से सीटू यह अपील करती है कि वह संघर्षों द्वारा प्राप्त एकता को बनाए रखे व उसे और मजबूत करे तथा मेहनतकश व जनवादी जनता के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर वाममोर्चा सरकार की रक्षा व जनवाद को बनाए रखने के लिए संघर्ष को और आगे बढ़ाए. □

त्रिपुरा : सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस त्रिपुरा के मजदूरवर्ग व जनता को आवश्यक सेवा अध्यादेश व कीमत वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध में 14 सितंबर को सफलतापूर्वक बंद आयोजित करने के लिए बधाई देती है.

मजदूर वर्ग व जनता ने कांग्रेस (आई) के समर्थकों को भड़कावे की कार्यवाहियों व तनावभरी स्थिति जो जलाईबाड़ी में उनकी सांठगांठ से हुयी पुलिस गोलीबारी, जिनमें तीन जानें गयीं थी व कई घायल हुये थे, से उत्पन्न हुयी थी, के प्रति प्रशंसनीय नियत्रण प्रदर्शित किया था. उन्होंने 'बंद' को सफल बनाया व बंद का विरोध करने वालों को करारी मात दी. जनवादी आंदोलन के उन नेताओं को सीटू श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो पुलिस गोलीबारी में मारे गये थे और उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदना भेजती है.

एस्मो, कीमत वृद्धि व सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग व जनवादी जनता के बढ़ते संघर्षों की ओर सीटू भारत सरकार का केंद्रित ध्यान आकृष्ट करती है और मांग करती है कि सरकार मजदूरों के बुनियादी अधिकार—हड़ताल के अधिकार को छीनने की प्रवृति को त्याग दे तथा अपनी नीतियों को बदले. □

अंगोला के खिलाफ युद्ध की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 2 सितंबर को यह बयान जारी किया है :

दक्षिण अफ्रीका के जातिभेदी निजाम द्वारा अंगोला की जनता पर बिना किसी भड़कावे के हमला करने तथा उन पर पूर्ण रूप से युद्ध थोप देने को सीटू निंदा करती है. रंगभेद की नीति के खिलाफ अफ्रीकी जनता के बढ़ते संघर्ष का बेतहाशा फांसी देने व दमन के अन्य बर्बर कदमों द्वारा दमन न कर सकने के बाद दक्षिण अफ्रीका की जातिभेदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में व्यक्त विश्वमत की परवाह न करते हुए इस क्षेत्र के काले लोगों को आतंकित करने की नाकाम कोशिश की है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल करने और इस प्रकार काले लोगों को इस कत्लेआम को खत्म करने के लिए कदमों को रोकने के लिए अमरीका के रीगन प्रशासन की सीटू भर्त्सना करती है. थैचर सरकार ने सुरक्षा परिषद में मतदान में भाग न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीकी जातिभेदी सरकार के इस घिनौने अपराध का समर्थन किया है.

सीटू देश के मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह दक्षिण अफ्रीकी जातिभेदी निजाम द्वारा शुरू की गयी जंग के खिलाफ प्रतिरोध में अपनी शक्तिशाली आवाज बुलंद करके दक्षिण अफ्रीका व अंगोला के अपने भाइयों के साथ एकजुटता का इजहार करें. □

बंबई सम्मेलन के आह्वान पर

मजदूरों के बढ़ते कदम

महंगाई तथा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ एकताबद्ध संघर्ष छेड़ने के, चार जून के बंबई सम्मेलन के, आह्वान को मजदूर वर्ग का कितना जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है, इससे यह जाहिर है कि संघर्ष का पहला चरण, राज्यस्तर की अभियान समितियां गठित करना तथा राज्य क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन करना आदि, तीन महीनों में ही सफलतापूर्वक पूरा हो गया. अब तक प्राप्त खबरों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में अभियान समितियां गठित करके राज्य स्तर के सम्मेलन हो चुके हैं और उनमें निम्नलिखित संगठनों ने भाग लिया है :—

केरल (त्रिवेन्द्रम)—अगस्त 9. सी. आई. टी. यू., एटक, यू. टी. यू. सी. एच एम एस, इंटक (यू).

महाराष्ट्र (पुणे)—अगस्त 31. सी. आई. टी. यू., एटक एच एम एस, बी एम एस, यू. टी. यू. सी.

राजस्थान (जयपुर)—अगस्त 30. सी आई टी यू, एटक, एच एम एस, बी एम एस, इंटक (दारा).

तमिलनाडु (कोयबतूर) अगस्त 31. सी आई टी यू, एटक, एच एम एस, टी एन टी यू सी (जनता).

पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)—अगस्त 31 सी आई टी यू, एटक, यू टी यू सी, टी यू सी सी.

त्रिपुरा (अगरतला)—सितम्बर 6. सी आई टी यू, एटक, यू टी यू सी.

मध्य प्रदेश (भोपाल)—सितम्बर 6. सी आई टी यू, एटक, एच एस एस, बी एम एस, यू टी यू सी (ले.स.).

आसाम (गोहाटी)—सितम्बर 6. सी आई टी यू, एटक, बी एम एस, यू टी यू सी (ले.स.).

आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)—सितम्बर 9. सी. आई. टी. यू., एटक, एच एम एस बी एम एस.

हरियाणा (करनाल)—सितम्बर 13. सी. आई. टी. यू., एटक, बी एम एस, यू टी यू सी (ले.स.).

बिहार (पटना)—सितम्बर 20. सी आई टी यू, एटक, बी एम एस, यू टी यू सी (ले.स.).

उत्तर प्रदेश (लखनऊ)—सितम्बर 20. सी आई टी. यू., एटक, यू टी यू सी, एच एम एस, बी एम एस.

उड़ीसा (कटक)—सितम्बर 20. सी आई टी यू, एटक, एच एस एस, बी एम एस, यू टी यू सी (ले.स.).

सी. आई. टी. यू. की तरफ से, महासचिव पी. राममूर्ति ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के सम्मेलनों को संबोधित किया, उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के, सचिव एम. के. पंधे ने बिहार के, सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने उड़िसा के तथा उपाध्यक्ष मनोरंजन राय ने पश्चिम बंगाल के सम्मेलनों को सम्बोधित किया.

इन सम्मेलनों ने बम्बई सम्मेलन के फैसलों के अनुरूप प्रस्ताव पास किए और हड़तालों पर पाबन्दी लगाने वाले अनिवार्य सेवा अध्यादेश की भर्त्सना की. वक्ताओं ने सभी वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों के असली कारणों को बताते हुए सरकार की विदेशी मदद पर निर्भरता, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से गठजोड़ और मजदूरों को अनुशासनबद्ध करने के लिए इसकी घोर मजदूर-विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे किसानों और खेत मजदूरों की मांगें उठाएं और महंगाई तथा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में उनके साथ मोर्चा कायम करें.

इन सम्मेलनों की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि राज्य अभियान समितियों ने जबर्दस्त प्रचार अभियान चलाया. हजारों की संख्या में पोस्टर और पर्चे छपवाए. बम्बई सम्मेलन के प्रस्ताव को राज्य व क्षेत्रीय भाषाओं में छपवाकर बेचा. और बड़े पैमाने पर मजदूरों को लामबद किया. इन सम्मेलनों को आयोजित करने वाली केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के अलावा आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र, जैसे बैंक, जीवन बीमा, आमबीमा, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी, रेलवे, डाक एवं तार, जहाजरानी, सड़क परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के वेतनभोगी मजदूर और कर्मचारी भी इतनी भारी संख्या में शामिल हुए कि सम्मेलन-हालों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची. इन सम्मेलनों के बाद हुई रैलियां और जन सभाएं भी इतनी ही प्रभावशाली थीं.

यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि इंटक (आई) और डी. एम. के. तथा ए. आई. डी. एम. के. से संबंधित ट्रेड यूनियन संगठनों ने इन सम्मेलनों में भाग न लेकर यह साफ कर दिया कि वे शासक पार्टी के राजनीतिक दुमछल्ले मात्र हैं. इन संगठनों ने 1978 में औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ सम्मेलन में भाग लिया था और संसद पर मजदूरों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे. इसी प्रकार आसाम में पृथकतावादी तत्वों ने गोहाटी में सम्मेलन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश की और कई डेलीगेटों पर शारीरिक रूप से हमला किया. इसके बावजूद, मजदूरवर्ग की यह एकता जिला एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिये नीचे तक कायम हो रही है और यह प्रक्रिया पूरे अक्तूबर तक चलती रहेगी. तीन नवम्बर को 'प्रतिरोध एवं मांग दिवस' मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. इस दिन संयुक्त प्रदर्शनों, मोर्चों, रैलियों आदि के जरिये जनता के सभी मेहनत कश हिस्सों को लामबद किया जायगा.

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा

'एस्मो' के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 8 सितंबर को नयी दिल्ली में हुई अपनी बैठक में आवश्यक सेवा अध्यादेश (एस्मो), जो संसद के मौजूदा अधिवेशन में कानून बन जायगा, को वापस लेने की अपनी मांग के समर्थन में संघर्ष को तेज करने का फैसला लिया. इंटक के अध्यक्ष जे एस दारा ने बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक ने यह नोट किया कि महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सफलतापूर्वक राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और अन्य राज्यों में सितंबर के अंत व अक्तूबर के शुरू में सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे. कीमतवृद्धि व सरकार की मजदूरवर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के आह्वान को मजदूर वर्ग द्वारा पूरी ताकत दिये जाने का बैठक ने स्वागत किया.

बैठक ने 3 सितंबर के केरल बंद की सफलता के लिए केरल के मजदूर वर्ग का अभिनंदन किया तथा उन्हीं मुद्दों पर पश्चिम बंगाल की ट्रेड यूनियनों द्वारा 11 सितंबर को राज्य बंद करने के फैसले का समर्थन किया. समिति ने इस पर संतोष व्यक्त किया कि पिछली जून में बंबई सम्मेलन ने जो आंदोलन छेड़ा था वह धीरे-धीरे समूचे देश में जोर पकड़ रहा है.

समिति ने देश के मजदूर वर्ग का फिर से आह्वान किया है कि 3 नवंबर को प्रदर्शन किए जाएं और समूचे देश में मांग व विरोध दिवस मनाया जाए जिससे बंबई सम्मेलन द्वारा उठायी गई मांगों, जैसे आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी, किसानों के लिए ऊंची कीमतें व खेतिहर मजदूरों के लिए ज्यादा वेतन, कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन, महगाई की पूरी भरपाई, छंटनी व विकिटमाइजेशन पर रोक, अधिक बोनस, सूचकांक में सुधार, ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व अन्य दमनकारी कानूनों को वापिस लेना, को लोकप्रिय बनाया जा सके. उस दिन राजभवनों, जिला मुख्यालयों और अन्य सरकारी दफ्तरों पर कीमतवृद्धि व आवश्यक सेवा अध्यादेश जैसे काले कानूनों के खिलाफ मजदूर वर्ग की आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन किए जाएंगे.

समिति ने यह फैसला किया कि इन मांगों के समर्थन में 23 नवंबर को संसद पर मजदूरों का भारी प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इस दिन देश भर के तमाम उद्योगों के लाखों मजदूर दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय सरकार को कीमतवृद्धि व मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ चेतावनी दी जाएगी तथा एक दिन की देशव्यापी हड़ताल की तारीख पर विचार किया जाएगा.

समिति ने भारत में संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार के दमन के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दिए जाने वाले ज्ञापन पर विचार किया. इसने यह तय किया कि ज्ञापन एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाएगा.

राष्ट्रीय अभियान समिति की अगली बैठक एक नवंबर को नयी दिल्ली में होगी. बैठक में इंद्रजीत गुप्ता, सांसद, पार्वती कृष्णन (एटक), शांति पटेल, सांसद (एच एम एस), एम के पंधे, नृसिंह चक्रवर्ती (सीटू), आर के भक्त, जी. एस. वशिष्ट (बी एम एस), जे एस दारा (इंटक), सुशील भट्टाचार्य, सौरेन भट्टाचार्य (यू टी यू सी) प्रितीश चंदा, ज्ञानसिंह (यू टी यू सी एल एस) तथा अमर चक्रवर्ती, सांसद (टी यू सी सी) ने भाग लिया. □

आई एम एफ से ऋण पर अर्थशास्त्रियों द्वारा चिन्ता

पश्चिम बंगाल सरकार के आमंत्रण पर भारत के 23 प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने कलकत्ता में 7-8 अगस्त को हुए एक सम्मेलन में भाग लिया. यह सम्मेलन देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने और केंद्र को आवश्यक कदम उठाने के लिए सिफारिश करने के लिए बुलाया गया था. इस गोष्ठी की अध्यक्षता डा० आई. एस. गुलाटी ने की. आर्थिक स्थिति और केंद्र की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने के बाद इन अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय सरकार को 11 सूत्री सुझाव पेश किए.

अर्थशास्त्रियों ने 8 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सरकार द्वारा आई एम एफ से 5,000 करोड़ रुपये का भारी ऋण लेने और देश की सुरक्षित विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट पैदा करने वाली केंद्र की आयात नीति पर गहरी चिन्ता प्रकट की. उन्होंने केंद्रीय सरकार को चेतावनी दी कि आई एम एफ द्वारा इस प्रकार के ऋण, उधार लेने वाले देशों पर अपनी आर्थिक निरंकुशता लादकर ही दिए जाते हैं. ऐसे ऋणों को प्राप्तकर्ता देश के लिए आत्महत्या की संज्ञा देते हुए डा० गुलाटी ने कहा कि आई एम एफ की नीति यह है कि वह ऐसे निर्णय लेने से पहले यह शर्त लगता है कि गरीब जनता के लिए खाद्य अनुदान, काम के बदले अनाज आदि सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए. □

सीटू प्रतिनिधि इटली रवाना

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स एसोसिएशन (सीटू) के संयुक्त सचिव एम. राजन आई. एल. ओ. द्वारा तीन महीने के लिए आयोजित श्रमिक शिक्षा के तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 20 सितंबर को दिल्ली से टुरीन (इटली) को सीटू की ओर से रवाना हो गए हैं. प्रशिक्षण के तहत वे पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका भी जाएंगे. □

जलमोर्चा मजदूरों की अखिल भारतीय आंदोलन की तैयारी

भारत की जल परिवहन वर्कर्स फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति की मीटिंग कलकत्ता में 19-20 अगस्त को हुई, जिसमें जनवरी में हुए वेतन समझौते के दौरान बच गईं मांगों को मनवाने के लिए सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अखिल भारतीय अभियान चलाने का फैसला किया गया. इन मांगों को लेकर 30 सितंबर को रैलियां आयोजित की जाएंगी और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन पेश किए जाएंगे.

फेडरेशन के अध्यक्ष एम. एम. लारेंस ने मीटिंग की अध्यक्षता की. फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के. के. राय गांगुली ने हालदिया में हुई पिछली कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग के बाद की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. विभिन्न केन्द्रों के साथियों ने रिपोर्ट पर बोलते हुए अपने अनुभवों और विभिन्न केंद्रों में बढ़ती हुई गतिविधियों का उल्लेख किया. सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे और सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने भी बहस में हिस्सा लिया. कामरेड बी. टी. रणदिवे ने ट्रेड यूनियन आंदोलन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और बंदरगाह एवं गोदी मजदूरों तथा नाविकों का, मौजूदा मांगों को लेकर एकताबद्ध संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया. उन्होंने तानाशाही के खतरे और भारत की सीमाओं पर साम्राज्यवादी साजिशों का भी जिक्र किया.

मीटिंग ने भारत की फारवर्ड सीमेन यूनियन द्वारा पेश किए गए 7 सूत्री मांगपत्र का समर्थन किया और अगले नवंबर में सभी नाविकों की एक दिन की हड़ताल करने का फैसला किया.

कार्यकारिणी कमेटी ने संयुक्त आंदोलन के सभी प्रोग्रामों को सभी बंदरगाहों में पूरा करने के लिए जोरदार तैयारियां करने का फैसला किया.

बीस अगस्त को मजदूरों की एक जनसभा की गई जिसे अन्य वक्ताओं के अरिरिक्त बी. टी. रणदिवे, कृष्णपद घोष और एम. के. पंधे ने संबोधित किया. □

निर्माण व उप-ठेका मजदूरों की बैठक

निर्माण उद्योग में मौजूदा परिस्थितियों पर विचार करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में फैसला करने के लिए निर्माण उद्योग के मजदूरों की एक मीटिंग 25 अगस्त को बेलूर में हुई. सी. आई. टी. यू. की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सेक्रेटरी शान्ति घटक ने मीटिंग की अध्यक्षता की. सी. आई. टी. यू. सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने कन्नानोर में हुई पिछली मीटिंग के बाद की घटनाओं की समीक्षा की. सी. आई. टी. यू. सेक्रेटरी नृसिंह चक्रवर्ती ने निर्माण और उप-ठेका मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डाला. इन समस्याओं के समाधान के लिए सी. आई. टी. यू. द्वारा एक अखिल भारतीय आंदोलन के जरिये निर्माण उद्योग के मजदूरों को इकट्ठा करने की जरूरत को महसूस किया गया. इसी बीच एच. एस. सी. एल. में ज्वाइंट फोरम की सब-कमेटी की मीटिंग 28 अगस्त को नई दिल्ली में हुई थी. इस कमेटी में सी. आई. टी. यू. के प्रतिनिधि के. रामदास आचारी ने एक पत्र पेश किया, जिसमें हैदराबाद, कुद्रेमुख, ओबरा आदि में छंटनी किए गए सभी मजदूरों को नौकरी की निरंतरता सहित बहाल करने की मांग की गई थी. प्रबंधकों, इंटक तथा एटक के प्रतिनिधियों ने इस पत्र का विरोध किया. परिणामस्वरूप, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. कुद्रेमुख के 49 मजदूर जिन्हें एस. यू. पी. ए. में गिरफ्तार किया गया था, 25 अगस्त को रिहा कर दिए गए. उन्हें कुद्रेमुख आइरन ओर प्रोजेक्ट में रखवाने की सी. आई. टी. यू. की कोशिशें बराबर जारी हैं. □

इंजीनियरिंग मजदूरों की बैठक

बेलूर में 25 अगस्त को इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियनों की अखिल भारतीय को-आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई. इस मीटिंग का उद्देश्य विभिन्न प्रांतों में इंजीनियरिंग उद्योग की परिस्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना था ताकि उसके आधार पर मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक संयुक्त आंदोलन खड़ा किया जा सके. इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, राजस्थान, पंजाब, यू. पी., दिल्ली, आसाम, गुजरात, मध्यप्रदेश और कर्नाटक से सदस्यों ने भाग लिया.

मीटिंग की अध्यक्षता रबिन मुखर्जी ने की. सी. आई. टी. यू. के सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने मीटिंग में भाग लिया. को-आर्डिनेशन कमेटी के संयोजक शांति घटक ने मार्च में हावड़ा में हुई इंजीनियरिंग मजदूरों की अखिल भारतीय कनवेंशन के फैसलों के बारे में रिपोर्ट पेश की.

इजीनियरिंग उद्योग में छंटनी, ले-आफ और क्लोजर की गंभीर स्थिति बनी हुई है. विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों में मिलने वाले वेतनों में काफी अंतर है. मीटिंग ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा एम. के. पंधे को इंजीनियरिंग पेनल का अध्यक्ष मनोनीत करने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इंजीनियरिंग उद्योग में सेफ्टी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला लिया. को-आर्डिनेशन कमेटी की अगली मीटिंग कलकत्ता में 9 और 10 नवंबर को होगी जिसमें इंजीनियरिंग उद्योग की कार्यप्रणाली के बारे में अखिल भारतीय रिपोर्ट का मसविदा तैयार किया जाएगा. इंजीनियरिंग मजदूरों की एक कनवेंशन करने का फैसला भी लिया गया. यह कनवेंशन बंबई में होगी और तारीख कोआर्डिनेशन कमेटी तय करेगी. □

कामगार महिलाओं का अखिल भारतीय सयुक्त सम्मेलन

कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय को-आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 24 अगस्त को बेलूर में समपन्न हुई. सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने इसमें भाग लिया. मीटिंग में 22 नवम्बर को दिल्ली में कामगार महिलाओं का एक कन्वेंशन आयोजित करने का फैसला लिया गया. इस कन्वेंशन में कामगार महिलाओं की आम तथा विशिष्ट समस्याओं और ट्रेड यूनियन आंदोलन में कामगार महिलाओं की भूमिका पर विचार किया जाएगा.

प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि दिल्ली, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कामगार महिलाओं की गतिविधियां संतोषजनक तरीके से बढ़ रही हैं. जे. एम. इलेक्ट्रोनिक्स, फरीदाबाद के संघर्ष का को-आर्डिनेशन कमेटी ने सफलता पूर्वक नेतृत्व किया. पुलिस हस्तक्षेप के विरुद्ध एक संयुक्त गेट मीटिंग की गई और जुलूस निकाला गया. चार कार्यकर्त्ताओं के निलम्बन और 50 कामगारों के ले-आफ के खिलाफ 57 दिन का धरना दिया गया, जिससे प्रबंधकों को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा. तामिलनाडु में बालगृह और परिवहन की सुविधाएं प्राप्त करके आरंभिक जीत हासिल की गई. को-आर्डिनेशन कमेटी ने वेलूर की नर्सों के संघर्ष का नेतृत्व किया. महाराष्ट्र में को-आर्डिनेशन कमेटी ने महिलायों पर अत्याचारों के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन आयोजित किए.

मीटिंग में, सी. आई टी. यू. के दिशा-निर्देश में अध्ययन-कक्षाएं लगाने का फैसला किया गया.

मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि बम्बई सम्मेलन के फैसले के अनुसार महंगाई तथा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 23 नवम्बर को 'संसद पर प्रदर्शन' में भाग लेने के लिए कामगार महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए.

मीटिंग का समापन करते हुए बी. टी. रणदिवे ने कहा कि "महिला आंदोलन के प्रति उदासीनता और विरोध, जो कि टी. यू. आन्दोलन में एक सामन्तवादी भटकाव है, को हम कम करके आंकते हैं. पिछले 20 वर्षों में महिलाएं मजदूर वर्ग का हिस्सा बन गई हैं. हमें महिलाओं को मजदूरवर्ग के हिस्से के रूप में समझना होगा. कामगार महिलाओं की समस्याएं बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं और ट्रेड यूनियन आंदोलन को उन पर ध्यान देना चाहिए. ईसाई चर्च और इसी प्रकार की कुछ स्वार्थी पार्टियों और ग्रुपों ने इस ओर ध्यान दिया है और वे महिला आंदोलन में सक्रिय हैं और वामपंथी नारों के साथ अति वामपंथी रुख अख्तियार कर रहे हैं. वे संघर्षों को 'पुरुष बनाम महिला' का सुधारवादी रूप दे देना चाहते हैं. आधुनिक समाज में, मजदूर वर्ग नेतृत्वकारी हिस्सा है और कामगार महिलाएं महिला आंदोलन का अगुआ हिस्सा हैं. इसलिए हर प्रकार के भटकावों के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना होगा. हमें महिलाओं को यह बताना होगा कि उन्हें अपने संघर्ष को मजदूर वर्ग के संगठित संघर्ष का हिस्सा बनाना चाहिए. उन्हें अपनी यूनियनों में सक्रिय होना चाहिए. हमारा मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि हम महिलाओं को यूनियन के झंडे के नीचे लामबन्द करें और उनमें से यूनियन से अलग रहने की भावना को दूर करें. हमें सी. आई. टी. यू. में तथा यूनियनों में महिलाओं के बीच काम पर जोर देना चाहिए. लेकिन हमें यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि महिलाओं का स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन न बने. □

भेदभाव खत्म करने की कोआर्डिनेशन कमेटी द्वारा मांग

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन की सेक्रेटरी विमला रणदिवे ने 31 अगस्त को यह बयान जारी किया.

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन (सीटू) इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया के प्रबंधकों द्वारा आयु सीमा व संतानोत्पत्ति को लेकर विमान परिचारिकाओं के खिलाफ लंबे अर्से से किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ विमान परिचारिकाओं को उनकी शानदार जीत पर बधाई देती है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो 35 साल की आयु होने पर या गर्भ धारण करने पर विमान परिचारिकाओं की सेवाएं समाप्त करने संबंधी नियमों को भेदभाव पूर्ण तथा संविधान की धारा 14, 15 व 16 के विरूद्ध बताता है और उन्हें खारिज करता है, यह साबित करता है कि उनका संघर्ष सही था और इस संघर्ष को समूचे जनवादी आंदोलन, खासतौर से कोआर्डिनेशन कमेटी, ने पूरा पूरा समर्थन दिया था.

कोआर्डिनेशन कमेटी यह बताना चाहेगी कि विमान परिचारिकाओं के खिलाफ यह भेदभाव महिलाओं को 'वासना का प्रतीक' मानने की सामंती समझ का नतीजा है और एक महिला होने के बावजूद प्रधान मंत्री ने परिचारिकाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि "परिचारिकाओं के लिए 40 की आयु बहुत ज्यादा है; भारत में कोई कोई ही महिला अपना आकर्षण व गठन बनाए रख पाती होगी". यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि विभिन्न सेवाओं व जीवन के दूसरे अनेक क्षेत्रों में जैसे नौकरियों, पदोन्नतियों में ऐसा भेदभाव जारी है और उन्हें उनका सामाजिक स्तर व मातृत्व का अधिकार नहीं दिया जाता हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको मान्यता दी है.

कोआर्डिनेशन कमेटी भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों को इस फैसले को लागू करने के लिए तथा विमान परिचारिकाओं को 'वासना का

[शेष पृष्ठ सात पर]

ए. आई. आर. एफ. के नाम पी राममूर्ति का संदेश

मैं 14 सितम्बर 1981 को मथुरा में आयोजित ए आई आर एफ के 55वें वार्षिक सम्मेलन के उदघाट्न में आमंत्रण के लिए आप का धन्यवाद करता हूं. किन्तु मुझे खेद है कि पूर्व-व्यस्तता के कारण मैं समारोह में शामिल नहीं हो सकूंगा.

आपका सम्मेलन उस समय हो रहा है जबकि सरकार न केवल अनिवार्य उद्योग-जिसमें रेलवे भी शामिल है, के हड़ताल पर मनमानी पाबन्दी लगाने के अधिकार से सज्जित है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों की संयुक्त-परामर्श संस्था में कुछ राहत-कार्य के बदले में हड़ताल न करने का आश्वासन मांग रही है. सरकार ने पहले ही अतिरिक्त महंगाई भत्तें का 50 प्रतिशत रेलवे सहित सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का जमा रखने का प्रस्ताव रख दिया है. यह प्रस्ताव उस समय आया है जबकि जे. सी. एम. सहित सभी समझौते-तंत्र रेलवे में समाप्त के बराबर हो चुके हैं जसा कि मई 1981 में ए. आई. आर. एफ. की वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव और ए. आई. आर. एफ. द्वारा प्रदत्त बीकानेर समारोह के दरम्यान 10 सूत्री मांग पत्र सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने से विदित है.

मांगों के बारे में जबकि यह स्थिति है, उधर सरकार ने मनमाने अधिकारों के तहत ए. आई. आर. एफ. से संबद्ध यूनियनों के प्रमुख नेताओं सहित 10,000 रेलवे कर्मचारियों को पिछले एक साल के अन्दर शिकार बनाया है. कुछ दिन पहले ए. आई. आर. एफ. से संबद्ध एक संगठन के महासचिव तक को सेवा-निवृत कर दिया गया.

आपका सम्मेलन बढ़ती हुयी रेल दुर्घटनाओं एवं रेलवे कर्मियों सहित, आम जनता के प्राण हानि के कारणों पर ध्यान दे सकती है. यद्यपि अधिकारीगण 'मानविक विफलता' के नाम कर्मचारियों के मत्थे दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांशत: जनता में आम अनुभव यह है कि काम की रूप-रेखा में परिवर्तन, सुरक्षा नियमों की अवहेलना, भारी एवं तीव्र गति की ट्रेनों का संचालन, पुराने एवं टूटे रेलपथ एवं पुलों तथा गाड़ी व इंजन का पुन: नवीनीकरण नहीं होने से ही यह सारी दुर्घटनाएं होती हैं. विश्व बैंक यह दबाव डाल रहा है कि पूर्ण कम्प्यूटर तंत्र (टी. ओ. पी. एस. के नाम से दक्षिण अमेरिका रेलपथ में विदित) आई. बी. एम. के तीसरे चौथे स्तर के भारी कम्प्यूटर इस्तेमाल करके लागू किया जाए. इसका ए. आई. आर. एफ. ने बीकानेर सम्मेलन से विरोध किया है. अत: इस सम्मेलन में इन सब पक्षों पर विचार करना है एवं उचित फैसला लेना है.

ए आई आर एफ द्वारा 4 जून 1981 को 'बढ़ते मूल्यों एवं सरकारी श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन' में भाग लेने और 17 अगस्त को एस्मो के विरोध में 'काला दिवस' मनाने के कारण रेल मजदूर आंदोलन देश के मजदूर वर्ग आंदोलन की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया है. हमें आशा है कि ए आई आर एफ के 55वें सम्मेलन में 4 जून 81 के सम्मेलन के निर्णयों को सफल बनाने के लिए 23 नवम्बर 81 को संसद के सामने प्रदर्शन, 3 नवम्बर को समस्त रेलवे कर्मचारियों द्वारा 'विरोध एवं मांग दिवस' के रूप में मनाये जाने व देशव्यापी हड़ताल जिसकी तिथि राष्ट्रीय प्रचार समिति द्वारा तय की जायेगी इन सब में समूचे देश के रेल कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के लिए कदम उठाए जाएगें.

सी आई टी यू की जनरल काउंसिल जिसकी बैठक हाल ही में संपन्न हुई, ने एक प्रस्ताव अपनाया है जिसमें रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन दिया गया है. इसकी एक प्रति पहले ही आपको भेज दी गई है. मैं पुन: रेलवे कर्मचारियों का उनके जायज मांगों के लिए संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता हूं.

मैं आपके सम्मेलन के पूर्ण सफल होने की कामना करना करता हूं. अभिन्दन सहित. □

रेल दुर्घटनाओं के बारे में सरकार बेनकाब

ज्योतिर्मय बसु व अन्य नेताओं द्वारा उठाये गये 'काम रोको' प्रस्ताव पर 17 अगस्त को लोक सभा में और 24 अगस्त को राज्यसभा में हुई बहस ने रेलवे बोर्ड की मनमानी व्यवस्था का पर्दाफाश कर दिया है.

सदस्यों ने ए आई एल आर एस ए के साथ दस घंटे कार्यकाल के समझौते को एकतरफा तोड़ने सहित अन्य प्रश्नों की बौछार कर दी. सिकरी कमेटी की रिपोर्ट से रेलवे नियंत्रण की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया. रेलवे सरकुलरों के उदाहरण देते हुए सुरक्षा नियमों को भंग करने के उदाहरण दिये गये. श्रमिक सम्बन्ध, श्रमिक दमन, कार्यभार, सामानों और उपकरणों की कमी, श्रम योजनाओं की नीतियों में परिवर्तन के लिए जोरदार आवाज उठाई गई.

रेलमंत्री इन मुद्दों का उत्तर नहीं दे सके और अंतत: उन्होंने रेलवे सुधार समिति के कार्यक्रमों के तहत इन्हें ढकने का प्रयास किया. □

कोआर्डिनेशन कमेटी.....

[पृष्ठ छ: से आगे]

प्रतीक' समझकर उनका अपमान बंद करने के लिए मजबूर करे. सरकार कामगार महिलाओं के प्रति रवैये को पूरी तरह बदलने के लिए कदम उठाए और अपने सभी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में ऐसे भेदभाव को खत्म करे. □

युद्ध के बढ़ते हुए खतरे और शांति के लिए संघर्ष

जनरल काउंसिल की यह बैठक, तनाव-शैथिल्य को कमजोर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने के अमरीका के सोचे-समझे हुए अभियान पर गंभीरतापूर्वक गौर करती है. इस अभियान ने विश्व शांति को संकट में डाल दिया है और फौजी टकराव का खतरा पैदा कर दिया है जिसमें आणविक अस्त्रों तथा न्यूट्रान बमों का इस्तेमाल भी संभव है. हथियारों का भारी जखीरा खड़ा करने और अपने विभिन्न फौजी अड्डों का आधुनिकीकरण करने की अमरीकी कार्रवाई साफ तौर पर यही साबित करती है कि अमरीका तेजी से युद्ध की तैयारियां कर रहा है. 1982 के लिए रीगन प्रशासन द्वारा 136 अरब डालर का सुरक्षा बिल पेश किया गया है जो अमरीका के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फौजी कदम है और इससे पिछले साल की तुलना में 26.4 अरब डालर ऊंचा है. यह बैठक न्यूट्रान बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के रीगन प्रशासन के फैसले की कड़ी निंदा करती है. संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए नरसंहार करने का यह पैशाचिक हथियार मनुष्यता के विरुद्ध अपराध है.

अफगानिस्तान की जनता के प्रति सोवियत समर्थन तथा किसी भी बातचीत के लिए सोवियत फौजों की बिला शर्त वापसी को शर्त बनाकर रीगन प्रशासन निरस्त्रीकरण से संबंधित बातचीत को अनिश्चित काल के लिए टालता आ रहा है. ईरान से खदेड़े जाने के बाद अमरीका अब दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया में अपने अड्डों को तेजी से बढ़ा रहा है. दिएगो गार्सिया में वायु तथा समुद्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 30 करोड़ डालर का एक ठेका दिया गया है. इस अड्डे का काम पूरा हो जाने पर यहां 2,150 सैनिकों का जमाव होगा. इस अड्डे से भीमकाय सी-5 मालवाहक विमानों को उड़ाया जा सकेगा और उधर, समुद्री क्षेत्र में, विमानवाहक पोतों को शरण दी जा सकेगी. अमरीका ने अब ओमान, सोमालिया तथा केनिया में भी अड्डा बनाने की सुविधाएं हासिल कर ली हैं और वह इन देशों में अमरीकी ताकत को बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ डालर खर्च करने जा रहा है.

अमरीकी साम्राज्यवादी दक्षिण एशिया में यहूदीवादी इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारबंद कर रहे हैं और उसे ताकतवर व हमलावर ताकत के रूप में विकसित किया जा रहा है. अरब देशों की फूट तथा अमरीकी बढ़ावे से यहूदीवादी शासक इतने शेर हो गये हैं कि उन्होंने इराक के नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया और लेबनान पर अपने हमलों तथा लूट को बराबर जारी रखे हुए हैं. यहूदीवादियों को और अधिक फौजी मदद देने के अमरीकी फैसले ने पश्चिम एशिया के देशों के लिए तो साफ-साफ खतरा पैदा किया ही है, यूरोप के देशों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है. यूरोपीय देशों ने इस कदम के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है.

इस बैठक का दृढ़ विश्वास है कि अमरीकी शासकों के ये कदम यही बताते हैं कि यूरोप और एशिया के चारों ओर एक रणनीतिक घेरा खींचने की कोशिश की जा रही है. इसके पीछे एकमात्र नीयत यही है कि इस क्षेत्र में समाजवाद के प्रभाव को रोका जाय.

यह बैठक शांति की रक्षा के लिए जारी संघर्ष में आ रही गति पर ध्यान देती है और शांति की ताकतों—सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के देश जिसकी पहली कतारों में हैं—को पूरा-पूरा समर्थन देती है.

यह बैठक, अमरीकी साम्राज्यवादियों की ओर से युद्ध के बढ़ते हुए खतरे तथा विश्व शांति के लिए पैदा हुए संकट को पहचानने के लिए मजदूर वर्ग को आगाह करती है और मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह हमारे देश की तमाम जनता को एक और विश्व-युद्ध थोपने की इस घिनौनी साजिश के खिलाफ लामबंद करे. दुनिया-भर के मजदूर आंदोलन से नजदीकी सहयोग करते हुए युद्धोन्मादियों की साजिश को शिकस्त देना और विश्व शांति की रक्षा करना तभी संभव होगा.

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारबंद किये जाने पर

जनरल काउंसिल की यह बैठक, अमरीका द्वारा पाकिस्तान के फौजी शासकों को एफ-16 विमानों तथा दूसरे विकसित प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइलों) से बड़े पैमाने पर हथियारबंद किये जाने पर गहरी चिंता के साथ गौर करती है. इसकी खबरें भी मिली हैं कि पाकिस्तान के फौजी शासकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका से नवीनतम विध्वंसक विमान हासिल करने का सौदा भी पूरा कर लिया है. एफ-16 विमानों की तरह इस विमान में भी मिसाइलें लगी हुई हैं जो भारत के किसी भी हिस्से में मार कर सकती हैं. भारत की जनता को पाकिस्तान के शासकों द्वारा शुरू किये गये तीन-तीन युद्धों का सामना करना पड़ा है. स्वाभाविक रूप से इससे वह बहुत चिंतित है.

यह बैठक मजदूर वर्ग को आगाह करती है कि दिएगो गार्सिया में पूरे साजो-सामान से युक्त फौजी अड्डा कायम करने के बाद अब अमरीकी साम्राज्यवादी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में और भी नये-नये अड्डे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान इस क्षेत्र में उनकी इस रणनीति के केंद्र में है. पाकिस्तान पर "सोवियत खतरे" का मुकाबला करने के बहाने से अमरीकी साम्राज्यवादी, इस उपमहाद्वीप में पांव जमाने के लिए पाक फौजी तानाशाह को हथियारबंद कर रहे हैं. अमरीका जहां पाकिस्तान को अपनी नाभिकीय क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वहां भारत के मामले में तारापुर संयंत्र को यूरोनियम देने संबंधी पिछले समझौते को पूरा करने से इनकार कर रहा है. साफ तौर पर, इसके पीछे मंशा यही है कि भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय कि वह

सोवियत संघ के खिलाफ अमरीकी लाइन पर चले और उसकी हां में हां मिलाये. यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चीन का जनवादी गणतंत्र पाकिस्तान के फौजी तानाशाह को अमरीका द्वारा हथियारबंद किये जाने को समर्थन दे रहा है.

पाकिस्तान शासकों को दी जा रही अमरीकी मदद, वहां की जनता के खिलाफ तानाशाही शासन की ताकत को बढ़ाती है. इसके साथ-साथ इसके पीछे, एशियाइयों को एशियाइयों से लड़ाने की अमरीकी साजिश भी काम कर रही है. यह बैठक, लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए बहादुराना संघर्ष चलाने पर, पाकिस्तान के मजदूर वर्ग और वहां की जनता को तहेदिल से दोस्ताना मुबारकबाद देती है. पाकिस्तान और भारत दोनों की जनता को, दोनों देशों के बीच तनाव तथा युद्ध का, विरोध करना होगा.

यह बैठक आगाह करती है कि साम्राज्यवादी सहायता पर अपनी निर्भरता तथा तानाशाहीपूर्ण-जनविरोधी नीतियों के कारण शासक पार्टी, अमरीकी साजिशों का मुकाबला करने और देश की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए देश की जनता को लामबंद नहीं कर सकती. इसलिए, दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए, जनतंत्र में विश्वास रखनेवाली जनता को, हरकत में लाने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी मजदूर वर्ग और सर्वहारा ताकतों की ही है. यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी उपेक्षा करने का मतलब मजदूर वर्ग के लिए खुद अपने भविष्य को खतरे में डालना होगा. □

सीटू की जनरल काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव

छठी पंचवर्षीय योजना पर

1981 के 21 से 24 अगस्त तक हावड़ा में हुई सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक, योजनाओं की पूर्ण विफलता की ओर मजदूर वर्ग और देश की जनता का ध्यान खींचना चाहती है. छठी पंचवर्षीय योजना में यह सचाई खुलकर सामने आ गयी है. इस योजना में बड़े ही शर्मनाक तरीके से आम जनता पर हमला करने, उस पर और ज्यादा बोझ लादने की वकालत की गयी है जबकि, साधन-संपन्न वर्गों को रियायतें दी गयी हैं. योजना का दस्तावेज खुद अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और संकट की गहराई को बड़े साफ तौर पर दिखाता है.

योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया गया है कि हजारों करोड़ रुपये फूंकने के बावजूद, योजना के खत्म होने के बाद, कम से कम साढ़े 21 करोड़ लोग यानी कुल आबादी का 30% हिस्सा, गरीबी की रेखा के नीचे गुजर कर रहा होगा. यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि आबादी का 48% हिस्सा आज गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहा है. और, इस हालत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं. इसे देखते हुए योजना का यह दावा वास्तविक स्थिति को बहुत ही हल्का करके दिखाने की कोशिश है.

मिसाल के तौर पर, योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया गया है कि योजना के शुरू होने के समय तक 2 करोड़ 21 लाख लोगों को रोजगार दिये जाने का काम बाकी था. दस्तावेज में यह भी स्वीकार किया गया है कि योजना के पांच सालों के दौरान 3 करोड़ 20 लाख नये लोग रोजगार के बाजार में होंगे. योजना बनानेवाले 3 करोड़ लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने का शेखी भरा दवा कर रहे हैं. सचाई यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के बढ़ने की दर महज 8 लाख सालाना रही है, इसीलिए खुद-रोजगार का शगूफा छोड़ा गया है जो रोजगार की उम्मीद लगाये बैठे लोगों के साथ धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं है. रोजगार दफ्तरों के चालू रिकार्ड के अनुसार दिसंबर 1980 तक ऐसे लोगों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी थी. पिछली तमाम योजनाओं के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही रही है और यह योजना भी इस दिशा को बदल नहीं सकेगी.

योजना बनानेवालों का अनुमान है कि शहरी आबादी का करीब पांचवां हिस्सा कच्ची बस्तियों में रह रहा है. उनके अपने अनुसार 1985 तक ऐसे लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों के

सीटू सरकुलर नं० 22/81

प्रिय साथियों,

बेलूर-हावड़ा में 21-24 अगस्त, 1981 को संपन्न जनरल काउंसिल की बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाये हैं. इसने यह नोट किया है कि अमरीकी साम्राज्यवादी ज्यादा से ज्यादा मनमाने कदम उठा रहे हैं जिससे एक और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है. बैठक ने संपत्ति को बनाए रखते हुए नरसंहार करने के अमानवीय हथियार—न्यूट्रान बम को भारी मात्रा में बनाने के रीगन प्रशासन के फैसले की निंदा की है. पाकिस्तान को नवीनतम हथियारों से लैस करने के अमरीकी फैसले ने युद्ध के खतरे को हमारी दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. विश्व की बिगड़ती हुयी स्थिति की पृष्ठभूमि में ये कदम हमारे देश की स्वतंत्रता को धमकी हैं. युद्ध के बढ़ते हुए खतरे व शांति के लिए संघर्ष" तथा "अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारबंद करने" पर प्रस्तावों में इस विषय पर हमारे विचार दिये गए हैं. यह नोट किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बारे में जनता को सचेत करने तथा अभियान चलाने में और शांति व अपने देश की रक्षा के लिए संघर्ष में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग को तैयार करने में सीटू यूनियनें पीछे हैं.

राष्ट्रीय स्थिति पर, बैठक ने छठी पंचवर्षीय योजना पर एक प्रस्ताव अपनाया जो यह नक्शा पेश करता है

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

लिए आवास की सुविधा की जरूरत होगी. योजना बनानेवालों का इनमें से सिर्फ 21 लाख लोगों के लिए आवाससुविधा जुटाने का इरादा है. बाकी साढ़े तीन करोड़ लोगों को, अंतुले जैसे लोगों और उनके भाई-बिरादरों की मेहरबानी पर, कच्ची बस्तियों या फुटपाथों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जायगा. ग्रामीण क्षेत्र में आवास की स्थिति के सिलसिले में योजना बनाने वालों का अनुमान है कि एक करोड़ 45 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए मदद की जरूरत होगी. इनमें से 77 लाख को घर बनाने के लिए जमीनें दी जा चुकी हैं, लेकिन, जहां तक घर बनाने के लिए सहायता का सवाल है, वह सिर्फ 5 लाख 60 हजार परिवारों को ही दी गयी है.

योजना बनानेवालों ने किसानों के पक्ष में भूमि सुधारों को सख्ती से लागू किये जाने का सुझाव देने के बजाय 5 एकड़ से ऊपर की जोतों की अतिरिक्त भूमि के सिर्फ 15% हिस्से को अधिग्रहण का सुझाव देकर, एक तरफ बड़े जमींदारों को नयी रियायतें दी हैं और दूसरी ओर मंझोले किसानों पर हमला किया है. लगातार बढ़ती हुई कीमतों तथा छलांगें लगाकर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण खेतमजदूरों तथा किसानों की क्रयशक्ति लगातार घटती जा रही है. इसके बावजूद योजना बनानेवालों ने खेतमजदूरों को पूरा-पूरा रोजगार तथा उचित मजूरी दिलाने के लिए उचित कदम उठाने और किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतें दिये जाने का प्रस्ताव नहीं किया है.

समाज के इन गरीब तबकों को मदद पहुंचाने के नाम पर यह योजना तैयार की गयी है. इस योजना के एक हिस्से को तो दो अंकों में चल रही मुद्रास्फीति पहले ही चट कर चुका है. योजना को पूरा करने के लिए साधन जुटाने की जो योजना पेश की गयी है उससे पता चलता है कि इसका असली बोझ जनता पर ही पड़नेवाला है, जबकि पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन के नाम पर साधन-संपन्न वर्गों को इस बोझ से बरी रखा गया है. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को यह सलाह तो दी गयी है कि कीमतें बढ़ाकर अपने घाटों को कम करें, लेकिन इन घाटों की असली वजहों, भ्रष्टाचार कुव्यवस्था तथा क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न किये जाने आदि के खिलाफ कदम उठाये जाने की कोई सलाह नहीं दी गयी है. योजना बनानेवाले अपनी संपत्ति को पहले के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से फैला रहे, विदेशी तथा भारतीय इजारेदार घरानों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी नहीं करते. लेकिन, योजना बनानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों के उत्पादनों की कीमतें बढ़ाने, खाद्यान, खादों आदि पर दी जाने-वाली राहत (सब्सीडी) को खत्म करने और अप्रत्यक्ष कर थोपने आदि के जरिये लगभग 21,302 करोड़ के साधन जुटाने के लिए आम जनता पर हमला करना नहीं भूलते. इसके अलावा, योजना में 5,000 करोड़ के करीब के घाटे की, जो योजना के अंत तक इससे कम से कम दुगना तो जरूर ही बैठेगा, व्यवस्था रखी गयी है. इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तथा कीमतें और भी ऊपर चढ़ जायेंगी.

योजना बनाने वाले विदेशी सहायता पर निर्भर हैं. उनके अनुमान के अनुसार 10,000 करोड़ की नकद या कुल 20,000 करोड़ की विदेशी सहायता की जरूरत होगी. इस सहायता को हासिल करने के लिए जैसा कि विदेशी गठबंधनों की संख्या से साफ है, विदेशी इजारेदार कंपनियों को तरह-तरह की रियायतें दी गयी हैं. 1979 की तुलना में, स्वीकार किये गये विदेशी गठबंधनों की संख्या दुगनी होकर 596 के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी है. तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रानिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों समेत, अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी की घुसपैठ हो चुकी है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जा रही इन रियायतों ने हमारे देश को करीब-करीब गिरवी ही रख दिया है. इसके ऊपर से भुगतान संतुलन का बढ़ता हुआ घाटा है जिसके चलते सरकार को 4,500 करोड़ के कर्जे के लिए आइ एम एफ से सौदेबाजी करनी पड़ रही है. इस सारी स्थिति ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही ट्रेड यूनियन आंदोलन दोनों के लिए ही भारी खतरा पैदा कर दिया है. देश में हुए हड़ताल संघर्षों के बर्बर दमन तथा अनिवार्य सेवा अध्यादेश के जरिये हड़तालों पर पाबंदी लगाये जाने जैसे कदम इसीलिए उठाये गये हैं ताकि आइ एम एफ मेहरबान हो सके.

संगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा कर्मचारियों को हमलों का निशाना बनाने के लिए चुना गया है. योजना में पेश की गयी वेतन तथा आय नीति, उन पर वेतन जाम थोपने तथा मजूरी में कटौती करने की ही नीति है. बोनस को उत्पादन से जोड़ने की योजना का प्रस्ताव करके योजना बनानेवालों ने, बोनस के स्थगित मजूरी होने की धारणा पर हमला किया है. इसके अलावा उन्होंने यह भी सलाह दी है कि आइंदा मजूरी में कोई बढ़ोतरी उत्पादन के आधार पर हो. मजूर किसी एक कारखाने या उद्योग में यदि उत्पादन बढ़ा भी लेते हैं तब भी उन्हें अपनी मेहनत का उचित मुआवजा नहीं मिलनेवाला है. इसके लिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सारी की सारी अर्थ-व्यवस्था नहीं सुधर जाती. आय की असमानताओं के नाम पर योजना बनानेवालों ने, मजदूर और मजदूर की आय के बीच की असमानता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और इस असमानता को कम करने के नाम पर वेतनों में कटौती का प्रस्ताव किया है. लेकिन ये सारा स्वांग करने के बावजूद शोषक तथा शोषित वर्गों के बीच की भारी असमानताओं को कम करने और बड़े सरमाये-दारों, इजारेदारों, तथा जमींदारों की आमदनी पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

इसलिए, यह बैठक पूंजीवादी योजना की दीवालिया नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज करती है और मांग करती है कि, विदेशी ऋणों के भुगतान को फौरन स्थगित किया जाय, भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह के इजारेदार घरानों के राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीपतियों के ऊंचे मुनाफों पर प्रत्यक्ष कर लगाकर साधन जुटाये जायं, शोषक वर्गों तथा मेहनतकश जनता के बीच की आय की असमानता को कम करनेवाली सही तरह की वेतन तथा आय नीति लागू की जाय, अतिरिक्त भूमि का गरीब किसानों के बीज वितरण किया जाय, किसानों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया जाय, खेतमजदूरों को उचित मजूरी दिलायी जाय, बेरोजगारों को बेकारी सहायता दी जाय और कमजोर तबकों की स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे कदम उठाये जायं. □

बंबई सम्मेलन तथा ट्रेड यूनियन एकता के काम

जनरल काउंसिल की यह बैठक 4 जून को बंबई में हुए "बढ़ती कीमतों तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन" के फैसलों का हार्दिक स्वागत करती है. इस सम्मेलन में, इसका आयोजन करनेवाले 8 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के अलावा 40 औद्योगिक फेडरेशनों ने शिरकत की थी. देश के विभिन्न हिस्सों से आये 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने एक कार्यक्रम पर आधारित प्रतिरोध कार्रवाई का फैसला लिया और

क. राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करने,
ख. 3 नवंबर 1981 को देश भर में प्रतिरोध तथा मांग दिवस मनाने,

ग. नवंबर 1981 के तीसरे हफ्ते में संसद पर मजदूर मार्च और
घ. तमाम उद्योगों में एक दिन की हड़ताल कार्रवाई का फैसला लिया.

सम्मेलन में तैयार किये गये मांगपत्र में किसानों, खेतमजदूरों, मजदूरों और भीषण मुद्रास्फीति तथा आसमान पर चढ़ती कीमतों की मार से बदहाल देश की सारी की सारी जनता की मांगों को शामिल किया गया है.

यह बैठक इन कामों को पूरा करने में उत्साह के साथ लगे देश भर के मजदूर वर्ग का हार्दिक अभिनंदन करती है और सीटू से संबद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे नीचे के स्तर पर एकता को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें और राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकृत हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करायें.

सम्मेलन के बाद की घटनाओं, खास तौर पर अनिवार्य सेवा अध्यादेश को लादे जाने से, मजदूर वर्ग की एकजुट कार्रवाई तथा तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत अच्छी तरह साबित हो चुकी है. मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता को प्रभावित करने वाले मसलों पर मिल-बैठकर विचार कर सकने तथा आम सहमति के फैसलों के आधार पर फौरन हस्तक्षेप कर सकनेवाले ऐसे संयुक्त मंच की स्थापना के लिए सीटू के महासचिव कोशिश करते रहे हैं.

जनरल काउंसिल की यह बैठक, सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों के महासंघ (कन्फेडरेशन) के निर्माण के अपने आह्वान को, एक बार फिर दुहराती है और निर्देश देती है कि वक्त के इस तकाजे को पूरा करने के लिए, ऐसे संयुक्त मंच को बनाने के लिए नये सिरे से कोशिश की जाय. □

दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में

सी. आई. टी. यू. की जनरल कांउसिल की यह मीटिंग ट्रेड यूनियनों के विश्व फैडरेशय द्वारा हवाना में 10 से 15 फरवरी 1982 तक दसवीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस करने के फैसले का स्वागत करती है.

यह कांग्रस ऐसे समय में हो रही है जबकि विश्व पूंजीवाद का संकट और भी गहरा रहा है और इस संकट के बोझ को मजदूर वर्ग पर लादने की कोशिश की जा रही है. परिणाम स्वरूप रुपी पूंजीवादी देशों में मजदूरों पर वेतनमान के रूप में हमले हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सामाजिन सुरक्षा सुविधाओं में कटौती और मजदूरों के ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर हमले हो रहे हैं. इन देशों में मजदूर वर्ग इन हमलों के खिलाफ एकताबद्ध प्रतिरोध फांदोलन संगठित कर रहा है.

विकासशील देशों का मजदूर वर्ग जहां अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लड़ रहा है, वहां अपनी आत्मानिर्भर अर्थ व्यवस्था बनाने तथा विकासशील देशों के हितो के लिए हानिकारक साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ भी संघर्षरत है.

विकसित पूंजीवादी तथा विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ संघर्ष एक नई तेजी पकड़ रहा है.

इसके विपरीत, समाजवादी देशों में मजदूर संकट विहीन समान में रहते हैं और उनका जीवन-स्तर लगातार ऊंचा उठता जा रहा है और इन देशों में बेकारी नाम की चीज बिलकुल नहीं है.

साम्राज्यवादी देशों में शस्त्र-उद्योग में तेजी और नाभिकीय अस्त्रों के निर्माण से दुनिया में एक और युद्ध का खतरा बढ़ गया है. पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग इस युद्ध के खतरे के विरुद्ध और निरस्गीकरण के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है.

इन परिस्थितियों में दसबीं विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक विशिष्ट घठना होगी, जिससे साम्राज्यवाद के खिलाफ और विश्व शांति के लिए संघर्ष में विश्वभर का मजदूर वर्ग बड़े पैमाने पर लामबन्द होगा.

सी. आई टी. यू. सभी संबंधित यूनियनों कर आह्वान करता है कि वे, विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सामने जो मुद्दे हैं, उन्हें जनमुद्दे बना दें ताकि भारतीय मजदूर वर्ग साम्राज्यवादी साजिशों तथा युद्ध के खतरों के खिलाफ और निरस्गीकरण तथा विश्वशांति के लिए विश्व त्यागी आंदोलन में अपनी सम्मानीय भूमिका अदा कर सके. □

हिमाचल प्रदेश सीटू का पहला सम्मेलन

ऊना जिले के मेहतपुर में 3 सितम्बर को संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश सी. आई. टी. यू. का पहला सम्मेलन राज्य के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक महत्त्वपूर्ण घटना है. इस राज्य में मजदूर आंदोलन बहुत ही कमजोर है और प्रतिकूल क्षेत्र होने के कारण विभिन्न केन्द्रों के साथ नियमित सम्पर्क रखना ही अपने आप में ही बहुत कठिन काम है. इसके बावजूद राज्य के सभी हिस्सों से 33 डेलिगेटों ने सम्मेलन में भाग लिया.

सी. आई. टी. यू. की हिमाचल प्रदेश तदर्थ कमेटी का गठन 1979 में राज्य की गतिविधियों में तालमेल कायम करने के लिए किया गया था. तदर्थ कमेटी ने गतिविधियों को ज्यादा कारगर तरीके से गाइड करने के लिए बाकायदा सम्मेलन करके राज्य कमेटी चुनने का फैसला किया.

सी. पी. आई. (एम) की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के सेक्रेटरी तारा चन्द ने लाल झंडा फहराया और डेलिगेटों ने शहीद मीनार पर फूल चढ़ाए.

सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्षमंडल चुना गया जिसमें ओ. पी. दत्ता, धनीराम और शाम लाल थे. डेलिगेटों द्वारा दिवंगत नेताओं और शहीदो को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सी. आई. टी. यू के सचिव एम. के. पंधे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने भारतीय मजदूर वर्ग पर बढ़ते हुए हमलों और पूरे देश में इसके खिलाफ संगठित किये जा रहे एकताबद्ध प्रतिरोध आंदोलन की समीक्षा की.

तदर्थ कमेटी के संयोजक कुलदीप सिंह ने राज्य में दो वर्षों की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर बहस में 11 साथियों ने भाग लिया. डेलिगेटों द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट स्वीकृत हुई.

सम्मेलन ने मजदूर वर्ग की ज्वलंत समस्याओं के बारे में कुछ प्रस्ताव पास किए और 13 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया. डी. एन. कपूर अध्यक्ष तथा धनीराम महासचिव चुने गए. □

चीन को शुभकामनाएं

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस चीन के जन गणतंत्र की स्थापना की 32वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन के मजदूर वर्ग व जनता को अपनी हार्दिक शुभ-कामनाएं भेजती है.

चीन के मजदूरवर्ग व जनता की क्रांति के बाद से, "सांस्कृतिक क्रांति" के काल की कमजोरियों के बावजूद, प्रशंसनीय उपलब्धियां भारत के मजदूर वर्ग के लिए महान गर्व का विषय है. सीटू को पूरा विश्वास है कि समाजवादी आधुनिकीकरण से चीन में उत्पादन क्षमता बहुत ही बढ़ेगी और जनता के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा.

भारत व चीन के बीच संबंधों में हाल ही में हुए सुधार से सीटू बहुत ही प्रसन्न है. यह आशा करती है कि यह प्रक्रिया और आगे जारी रहेगी तथा एशिया के दो महान देशों के बीच दोस्ताना संबंध और भी मजबूत होंगे.

सीटू प्रतिनिधिमंडल की पिछली जुलाई-अगस्त में चीन के जन गणतंत्र की यात्रा से सीटू व आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस के बीच मित्रता और भी मजबूत हुई है.

सीटू चीन के मजदूर वर्ग व जनता की समाजवादी निर्माण में और आगे तथा साम्राज्यवाद व युद्ध के खतरे के खिलाफ एवं विश्व शांति के लिए संघर्ष में चहुमुखी सफलता की कामना करती है. □

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	मई	जून	जुला.
बिहार			
जमशेदपुर	405	415	420
झारिया	403	405	409
कोडर्मा	426	437	450
मोंघाइर	442	456	473
नोआमुंडी	397	419	426
गुजरात			
अहमदाबाद	418	427	438
भाव नगर	442	448	454
हरियाणा			
यमुना नगर	456	468	477
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	460	459	465
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	449	452	462
भोपाल	451	461	470
ग्वालियर	464	467	481
इंदौर	475	480	487
महाराष्ट्र			
बंबई	442	450	459
नागपुर	440	454	459
शोलापुर	471	482	490
पंजाब			
अमृतसर	445	452	460
राजस्थान			
अजमेर	456	470	477
जयपुर	477	487	491
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	420	429	445
सहारनपुर	432	436	445
वाराणसी	480	484	491
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	436	440	444
कलकत्ता	399	406	408
दार्जीलिंग	348	350	360
हावड़ा	385	390	392
जलपाइगुरी	346	348	357
रानीगंज	415	442	425
दिल्ली	453	461	476
भारत	433	439	447

राष्ट्रीय समझौता लागू न करने पर कोयला मजदूरों का संघर्ष

अखिल भारतीय कोल वर्कर्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने रांची में 28-29 अगस्त को हुई अपनी मीटिंग में राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू न किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. शिक्षा, मेडिकल तथा मकान संबंधी प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है. अधिकतर कोयला खदानों में, यहां तक कि पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है. ग्रेच्युटी तथा कठिनाई भत्ते और सब-कमेटी की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू करने संबंधी सवालों को प्रबन्धकों ने अभी तक निश्चित नहीं किया है. समझौते के जिन प्रावधानों को लागू नहीं किया है, उन्हें लागू करवाने के लिए प्रबन्धकों पर दबाव डालने की खातिर फेडरेशन ने अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है.

अखिल भारतीय कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एम. के. पंधे ने मीटिंग की अध्यक्षता की.

मीटिंग में, कोयला खदानों में हुए पिछले द्विपक्षीय समझौते पर अमल न होने के बारे में 5000 बुकलेट छापने और उसे पूर्णतः लागू करवाने के लिए प्रचार अभियान छेड़ने का फैसला किया गया. पिछले अप्रैल में रानीगंज में हुई अखिल भारतीय कन्वेंशन के निर्देश के अनुसार मीटिंग ने फेडरेशन का संविधान स्वीकार किया. मीटिंग में यूनियनों के सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और फैसला किया गया कि सदस्यता अभियान तेज किया जाए ताकि पूरे देश में एक लाख सदस्य बनाए जा सकें. प्रत्येक यूनियन ने निश्चित कोटा लिया.

मीटिंग ने, पश्चिम बंगाल की ट्रेड यूनियनों के महंगाई, अनिवार्य सेवा सुरक्षा अध्यादेश तथा पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार की साजिशों के खिलाफ 11 सितम्बर को बंगाल बंद आयोजित करने के फैसले का स्वागत किया. सभी कोयला मजदूरों को बंद में शामिल होने और इसे कामयाब बनाने का आह्वान किया गया.

फेडरेशन ने कोल इंडिया लि० की रोजगार नीति की भर्त्सना की जिसके तहत कई हजार ऐसे लोगों, जिनकी भूमि छिन गयी है तथा विस्थापितों को नई खदानों में नौकरी से वंचित रखा जा रहा है. अंधाधुंध मशीनीकरण करने से खदानों में कई नौकरियों की सभावनाएं समाप्त हो गयी हैं. इसलिए मीटिंगों ने विस्थापित गांवों के प्रत्येक परिवार को नौकरी दिए जाने की मांग की.

मीटिंग में सी. सी. एल. तथा बी. सी. सी. एल. के प्रबन्धकों पर रानीगंज और धनबाद क्षेत्रों में सी. आई. टी. यू. के नेताओं के खिलाफ गुंडागर्दी भड़काने का आरोप लगाया गया. मीटिंग में, कोयला उद्योग में ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ विक्टिमाइजेशन की कार्यवाहियां रद्द किए जाने की मांग की गई.

मीटिंग ने वित्तमंत्री श्री वेंकटरमण के श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधुरी के नाम उस गुप्त पत्र पर चिन्ता जाहिर की जिसमें उन्होंने कोयला मजदूरों को और कोई रियायत न देने की बात लिखी है. मजदूरों का सरकार की इस साजिश के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया गया.

मीटिंग ने बम्बई में 3 जून को हुए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों के कन्वेशन के फैसलों का समर्थन किया और सभी कोयला मजदूरों को केन्द्रीय ट्रेड यूनियन की नेशनल कम्पेन कमेटी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया गया. नवम्बर के तीसरे सप्ताह में ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संसद पर प्रदर्शन में 300 मजदूरों का जत्था भेजने का फैसला लिया गया.

फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की अगली मीटिंग फरवरी में नागपुर में होगी.

इसी बीच इंटक ने कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी में से अपने नुमाइन्दों को वापिस बुलाने का फैसला लिया है. इंटक का यह फैसला मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठा कर इस कमेटी में ज्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए दबाव की नीति के तहत लिया गया है. कलकत्ता में 3 सितम्बर को हुई जे. बी. सी. सी. आई. की मीटिंग में मजदूरों के सभी प्रतिनिधियों ने इंटक के इस कदम को नामंजूर कर दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें क्योंकि कोयला मजदूरों की बहुत सी बाकी समस्याओं को हल करना है. □

सीटू सेक्रेटेरियट की बैठक

सीटू के सेक्रेटेरियट की नयी दिल्ली में 14 सितंबर को हुयी बैठक ने सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य कामरेड ए. बालसुब्रह्मण्यम की मृत्यु पर हार्दिक शोक व्यक्त किया. सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक में बेलूर में आयोजित जनरल काउंसिल की बैठक के साथ साथ हुई विभिन्न उद्योगानुसार बैठकों के फैसलों की समीक्षा की और उन्हें लागू करने के लिए कदमों पर विचार किया. इसने विभिन्न राज्यों में संयुक्त आंदोलनों की प्रगति व ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय प्रचार समिति की बैठकों में हुयी बातचीत पर विचार किया.

बैठक ने केरल व पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग को 3 व 11 सितंबर को कीमत वृद्धि व एस्मो के खिलाफ प्रतिरोध में कामयाब बंद आयोजित करने के लिए बधाई दी. इसने त्रिपुरा की ट्रेड यूनियनों के 14 सितंबर को हड़ताल आयोजित करने के फैसले और कर्नाटक व महाराष्ट्र में भी 21 सितंबर को हड़ताल करने के इसी तरह के फैसले का समर्थन किया.

दसवें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन में, जो हवाना (क्यूबा) में 10-15 फरवरी 1982 को आयोजित किया जा रहा है, भाग लेने के लिए बैठक ने सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति का नामांकन किया. □

संसद का ऐतिहासिक सत्र

सरकार की तानाशाहीपूर्ण वैधानिक कार्यवाही अर्थात् हड़तालों पर रोक लगानेवाले अनिवार्य सेवा बिल के खिलाफ लड़ते हुए दृढ़-निश्चयी एवं एकताबद्ध विपक्ष ने देर तक बैठने के संसद के अब तक के इतिहास के सारे रिकार्ड तोड़ दिए. जब अध्यक्ष ने 17 सितंबर को प्रात: 9 बजे बिल पर मतदान कराया तो अगली बैठक शुरू होने में केवल 7 घंटे बचे थे. विपक्ष की एकता को इस तथ्य से जाना जा सकता है कि लोकसभा में दो दिन की बहस के दौरान इस काले बिल के एक-एक प्रावधान पर हुई जी-तोड़ लड़ाई को सबका समर्थन मिला. विपक्ष ने इतना शक्तिशाली विरोध किया कि यहां तक कि एक कांग्रेस (आई) सांसद, रामचंद्रन, जिन्हें इस बिल का समर्थन करना था, ने स्वीकार किया कि यह बिल मजदूर वर्ग के गले नहीं उतर सकता.

गृहमंत्री के कपट का पर्दा तब खुल गया जब उन्होंने मजदूरों को अपना 'भाई' बताते हुए यह आश्वासन दिया कि "अतिरिक्त उत्पादन के लाभ को मालिकों से छीनकर मेहनतकश और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले कम भाग्यशाली लोगों में बांटा जायगा." लेकिन दृढ़ निश्चयी विपक्ष से दो-चार होते ही इंदिरा गांधी के नए पुजारी ने उस समय सरकार के असली तानाशाही चरित्र का पर्दाफाश कर दिया, जब विपक्ष को चुनौती देते हुए यह कहा कि "यदि आप लड़ना चाहते हैं, आप लड़ सकते हैं. लेकिन हम इसका जवाब देंगे." सी पी आई (एम) ग्रुप के नेता समर मुखर्जी ने दृढ़ वाणी और इस टिप्पणी के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 1977 में असमान विरोधी दलों को इकट्ठा कर दिया था और सरकार अब फिर उसी तरह की स्थिति पैदा कर रही है. राज्य सभा में इसी दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए पी. राममूर्ति ने घोषणा की कि इस बिल का उद्देश्य सरकार की पतनशील आर्थिक नीतियों के विरुद्ध उभरते हुए जन-आंदोलन के ज्वार भाटे को दबाना है, क्योंकि मजदूर वर्ग निस्संदेह इस संघर्ष की अगुवाई कर रहा है. संपूर्ण विपक्ष द्वारा तालियों की गड़-गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा कि आज मजदूर वर्ग को यह लड़ाई जारी रखते हुए आजादी और राष्ट्रीय एकता के झंडे को बुलंद करना होगा क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग है जो हमारी मेहनतकश जनता को नेतृत्व देने में समर्थ है. □

हरियाणा में हिसार टैक्सटाइल मिल्ज के मजदूरों के परिवारों पर हमले की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने पहली सितंबर को यह बयान जारी किया है :

देश के सबसे बड़े एकाधिकारी घरानों में से एक हिसार टैक्सटाइल मिल्स के प्रबंधकों की तथाकथित सुरक्षा गार्ड नियुक्त करके मजदूरों के परिवारों पर हमला करने के लिए और उन्हें उनके मकानों से बाहर निकाल फेंकने की कोशिशों के लिए सीटू भर्त्सना करती है. प्रबंधकों ने जब 16 अगस्त 1981 को बुनियादी वेतन पर पिछले समझौते को लागू किये बिना और महंगाई भत्ते, बोनस आदि की मांग, जिस पर पुराना समझौता दिसंबर 1980 में खत्म हो गया था, पर कोई समझौता किए बिना 3 मई से मिल में गैरकानूनी छंटनी कर दी तब सभी मजदूर व कर्मचारी 20 मई 1981 से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए थे.

सीटू हरियाणा सरकार की मालिकानपरस्त नीति की भी निंदा करती है कि इसने छंटनी को गैरकानूनी घोषित करने व प्रबंधकों को मजदूरों की जायज मांगों पर समझौता करने के लिए मजबूर करने की बजाए हड़ताल के बाद मामला ट्रिब्यूनल को सौंप दिया और इस प्रकार मिल्स की सभी पांचों यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे संघर्ष के दमन में प्रबंधकों के साथ सांठगांठ की. हरियाणा सरकार के ऐसे संरक्षण के कारण ही एकाधिकारी प्रबंधकों ने मजदूरों के परिवारों पर हमले को आतंक करनेवाली नई नीति अपनाई है. क्योंकि गैरकानूनी छंटनी को लगभग 4 महीने व हड़ताल के बाद 105 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं इसलिए सभी यूनियनों के नेता प्रधानमंत्री व श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिले कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें.

सीटू भारत सरकार से मांग करती है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे क्योंकि संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीना जा रहा है और मजदूरों के परिवार के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं. सीटू सभी मजदूरों से अपील करती है कि वे पहले ही प्राप्त एकता को सुरक्षित रखें और अपने जायज संघर्ष को जारी रखें और अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष को बर्बरतापूर्वक दमन करने के लिए एकाधिकारी घराने द्वारा अपनाई गई आतंककारी नीतियों से भड़कावे का शिकार न बने. □

गुप्त मतदान में सीटू यूनियन की जीत

बिहार के हजारी बाग जिले में सीटू से संबद्ध फायर ब्रिक्स व सिरामिक कामगार यूनियन ने गुप्त मतदान में भारी बहुमत से जीत हासिल की तथा इंटक एच एम एस, एच एम पी व एक असंबद्ध यूनियन को हराया.

इंडिया फायर ब्रिक्स एंड इंशुलेशन कंपनी के मजदूरों ने, जो सीटू यूनियन में संगठित हैं, 1978 से गुप्त मतदान द्वारा मान्यता के लिए कड़ा संघर्ष किया है. लेकिन जनता शासन ने मामले को लटका दिया व एच एम एस यूनियन को मान्यता देने की कोशिश की थी. बाद में कांग्रेस (आई) सरकार ने गुप्त मतदान के लिए इंकार कर दिया व इंटक यूनियन को मान्यता देने की कोशिश की. लेकिन मजदूरों के जुझारू संघर्ष ने सरकार को आठ अगस्त को गुप्त मतदान कराने के लिए बाध्य कर दिया. □

जे के रेयान व कानपुर जूट उद्योग में संघर्ष जारी

जे के रेयान वर्कर्स यूनियन (सीटू) और कानपुर जूट उद्योग मजदूर पंचायत (सीटू) के नेतृत्व में 200 मजदूर एक जुलूस में लखनऊ स्टेशन से चले और मुख्य मंत्री के घर के सामने 5 सितंबर को धरना दिया. जे के रेयान में संघर्ष दो साल पहले शुरू हुआ था जब प्रबंधकों ने ही इंटक की एक यूनियन बनवाकर उससे समझौता कर दिया था और सीटू यूनियन को नजरअंदाज कर दिया था. सरकारी मशीनरी की सहायता से प्रबंधकों ने मजदूरों पर भारी दमन ढाना शुरू कर दिया, नेतृत्व के एक हिस्से को बर्खास्त कर दिया तथा कई मजदूरों को गिरफ्तार कर दिया. जुलाई के बाद उन्होंने सैकड़ों मजदूरों की छंटनी कर दी. प्रबंधको ने नवंबर से जे के रेयान में कलोजर का नोटिस दे दिया है जबकि सरकार बिलकुल चुप बैठी है.

इसी प्रकार कानपुर जूट उद्योग के मजदूरों पर भी भारी दमन ढाया जा रहा. उद्योग में कई बार क्लोजर हो चुका है और सरकार की आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया है.

इसे मुद्दे का समाधान करने में उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी नाकामभावी ने मजदूरों को 16 सितंबर को नयी दिल्ली में श्रमशक्ति भवन में केंद्रीय श्रम मंत्री के दफ्तर के सामने धरना आयोजित करने के लिए मजबूर कर दिया. जे के रेयान व कानपुर जूट उद्योग के लगभग 100 मजदूरों ने धरने में भाग लिया. सीटू के सचिव एम. के. पंधे व निरेन घोष कद्रीय श्रम मंत्री से मिले व कलोजर के नोटिस की वापसी तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ सभी मुद्दों पर ससझौता करने की मांग की. □

इस्पात मजदूरों की अखिल भारतीय सम्मेलन

इस्पात वर्कर्स यूनियनों की अखिल भारतीय को-आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 30 अगस्त को जमशेदपुर में हुई, जिसमें 6, 7 और 8 नवंबर को इस्पात मजदूरों की अखिल भारतीय कनवेंशन दुर्गापुर में करने का फैसला हुआ. सी. आई. टी. यू. के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे कनवेंशन का उद्घाटन करेंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे.

मीटिंग की अध्यक्षता बासापद मुखर्जी ने की. एक मांगपत्र तैयार किया गया और 23 सितंबर को सभी इस्पात प्लांटों के प्रबंधकों को यह मांगपत्र देने और प्रदर्शन करने का फैसला किया गया. इस मांगपत्र को जनप्रिय बनाने और इसके लिए शक्तिशाली समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला हुआ. यह भी फैसला हुआ कि दूसरी साथी ट्रेड यूनियनों से संपर्क किया जाय ताकि वे भी इसी प्रकार की मांगें प्रबंधकों को दें. मौजूदा समझौता 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो जाएगा. यह फैसला हुआ कि आंदोलन खड़ा करके प्रबंधकों को उससे पहले ही मांगपत्र पर समझौता करने के लिए बाध्य किया जाए. मांगपत्र को जनप्रिय बनाने के लिए स्थानीय सम्मेलन करने और पर्चे बांटने का फैसला हुआ. एम.के. पंधे ने बंबई कनवेंशन के महत्व पर प्रकाश डाला और यह फैसला हुआ कि 23 नवंबर को ससद पर होने वाले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जाया जाए. □

सयुक्त आंदोलन के लिए विद्युत मजदूरों की तैयारी

बिजली उद्योग में काम कर रही सी. आई. टी. यू. की यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग 25 अगस्त को बेलर में हुई, जिसमें बिजली मजदूरों के वेतनमानों और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हुए हमलों की समीक्षा की गई. मीटिंग ने फैसला लिया कि बिजली उद्योग में काम करने वाली विभिन्न ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करने की कोशिशें की जाएं ताकि उनकी वेतन तथा काम के हालात संबंधी अन्य पुरानी मांगों का फैसला कराने के लिए पूरे देश में एक संयुक्त आंदोलन खड़ा किया जा सके. इस मीटिंग में सी. आई. टी. यू. के सेक्रेटरी ई बालानंदन ने भाग लिया □

सीटू सरकुलर

[पृष्ठ नौ से आगे]

कि किस प्रकार मजदूरों के वेतन, बोनस व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर चहुमुखी हमले हो रहे हैं जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एकाधिकारी घरानों और भूपतियों को सुविधाएं दी जा रही हैं और इस प्रकार यह देश में पूंजीवादी योजना के दिवालियेपन तथा कांग्रेस (आई) सरकार के पाखंडी दावों को बेनकाब करता है. "बंबई सम्मेलन तथा ट्रेड यूनियन एकता के लिए कार्य" पर प्रस्ताव एक पार्टी अधिनायकवादी शासन की स्थापना के लिए रूझान के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के कार्यों को और आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर देता है और सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों का एक कनफेडरेशन बनाने के आह्वान की पुनर्घोषणा करता है.

इसलिए हमारी संबद्ध यूनियनों को इन प्रस्तावों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और उन पर प्रचार अभियान शुरू करना चाहिए. युद्ध की गंभीर धमकी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और अभियान, फौरी जरूरत महसूस करते हुए, चलाया जाना चाहिए.

इन कार्यों को पूरा करने के लिए इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से हमारी पत्रिकाओं में छापा जा रहा है.

मुझे विश्वास है कि हमारी यूनियनें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखायेंगी और इस कार्य को पूरी गंभीरता के साथ लेंगी.

शुभकामनाओं सहित,

आपका साथी,

बी. टी. रणदिवे

अध्यक्ष

कामरेड ए बालसुब्रह्मण्यम

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज का सेक्रेटेरियट वर्किंग कमेटी के सदस्य व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो के भी सदस्य कामरेड ए. बालसुब्रह्मण्यम की पांच सितंबर की सुबह को हुयी असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करता है.

कामरेड बालसुब्रह्मण्यम ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिन्होंने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर दृढ़ता के साथ वर्ग संघर्ष के लक्ष्य की सदा रक्षा की. मजदूर वर्ग एकता के लक्ष्य को बुलंद करते हुये उन्होंने सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज के निर्माण में प्रमुख हिस्सा लिया और कलकत्ता में 28-30 मई को आयोजित स्थापना सम्मेलन में अध्यक्षमंडल में चुने गए उसी सम्मेलन में वे सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य चुने गए और अपनी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे. उन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति मजदूर वर्ग की, जो देश में गहराते आर्थिक संकट के कारण तीव्र संघर्ष के भंवर में आ रहा था, सामाजिक चेतना के विकास में लगायी. उनकी मृत्यु से देश ने एक महान ट्रेड यूनियन नेता और क्रांतिकारी खो दिया है.

कामरेड ए. बालसुब्रह्मण्यम के सम्मान में सेक्रेटेरियट सीटू का लाल झंडा झुकाता है और उनके शोकग्रस्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है. □

बंबई सम्मेलन....

[पृष्ठ तीन का शेष]

इन सम्मेलनों के जरिये प्राप्त मजदूरों और वेतनभोगी कर्मचारियों की एकता ने, तानाशाही शासन कायम करने और धीरे-धीरे आपातकाल की स्थितियां पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ मजदूर वर्ग को धुरी बनाकर प्रतिरोध का एक व्यापक मंच बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. इन बढ़ते हुए एकताबद्ध संघर्षों और ऊंची उठती हुई जनता की राजनीतिक चेतना से मौजूदा कांग्रेस (आई) कुशासन, जोकि आम आदमी पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहा है और इजारेदारों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और जमींदारों को एक के बाद दूसरी रियायतें दे रहा है, का एक व्यावहारिक, वामपंथी और जनवादी विकल्प निर्मित कर सकता है. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
नीरेन घोष सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित